Tirupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 23 February 2020
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-11 Issue - 38

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंच गई है। वे इलाके जो हिंसा से प्रभावित थे, वहां मरघट जैसा सन्नाटा पसरा है। रात में सड़कों पर रैपिड ऐक्शन फोर्स के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है।

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
प्लान बदला, इंदिरापुरम एक्सटेंशन के नाम से...

पेज नंबर 5
Bodies of two youths found in Bulandshahr...

TIRUPATIEYE

गोल्फ लिंक सोसायटी में फ्लॉवर शो शुरू

गाजियाबाद : एनएच–9 स्थित गोल्फ लिंक सोसायटी में 28 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय फ्लॉवर शो शुक्रवार से शुरू हो गया। इसका आयोजन लैंडक्रॉफ्ट व हॉर्टिकल्चर एंड फलोरीकल्चर सोसायटीज द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न शहरों के चटपटे व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। फ्लॉवर शो के आयोजक ललित जायसवाल ने बताया कि इस बार का आकर्षण किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, वर्टिकल गार्डन, लैंडस्कैपिंग, बोनसाई के साथ सेहत के लिए फायदेमंद पौधे है। रसायन रहित सब्जियों और फलों का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान योग, मेहंदी, टैटू, रंगोली, पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी हुई। स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम पेश किया। बच्चों के लिए जादू का शो भी दिखाया गया।

परमानंद वाटिका सेक्टर–12 वसुंधरा में गंदगी के ढेर, सिर्फ कागजों में हो रही सफाई

शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे निगम अधिकारी, नहीं है लाइट व पैदल पथ की व्यवस्था

वसुंधरा : वसुंधरा सेक्टर–12 में लिंक रोड किनारे बनी परमानंद वाटिका में जगह–जगह गंदगी के ढेर लगे हुए है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में नगर निगम को नहीं पता है। शिकायत के बाद भी नगर निगम यहां सफाई नहीं कर रहा है सिर्फ कागजों में ही सफाई हो रही है। यदि कोई एनजीओ इस परमानंद वाटिका को साफ–सुथरा बनाने के लिए गोद लेना चाहती है तो नगर निगम उसे गोद भी नहीं देना चाहता है और न ही वाटिका की साफ–सफाई की तरफ ध्यान दे रहा। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर के चार्टर प्रेसिडेंट डा.धीरज कुमार भार्गव ने बताया कि वे परमानंद वाटिका को गोद लेकर लोगों को एक स्वच्छ पार्क उपलब्ध कराना चाहते है। इसके लिए वे नगर निगम जोनल प्रभारी

सुनील राय, नगर आयुक्त दिनेश चंद व मेयर आशा शर्मा को परमानंद वाटिका गोद लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके है। कई माह बीत जाने के बाद भी नगर निगम की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। वे चाहते है कि वसुंधरा में रहने वाले लोगों को सुबह–शाम घूमने के लिए एक स्वच्छ पार्क मिल सके। इसके लिए वे वाटिका की सफाई के साथ ही लोगों के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन नगर निगम नहीं चाहता कि वसुंधरा के लोगों को साफ–सुथरा पार्क मिल सके। तभी तो निगम इसे गोद नहीं देना चाहता है और न ही इसकी साफ सफाई कराता। सेक्टर–12 वसुंधरा के लोग गंदगी में रहने को मजबूर है। इसमें न ही लाइट की व्यवस्था है और न ही लोगों के घूमने के लिए पैदल पथ की व्यवस्था है। निगम को परमानंद वाटिका की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आसपास झुग्गी–झोपड़ी भी बसी हुई है। जिससे यहां कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। ये कुत्ते आए दिन लोगों को काटते रहते है। नगर निगम को इन कुत्तों को भी पकड़ना चाहिए।

वसुंधरा सेक्टर–10ए के सामने ग्रीन बेल्ट पर हो रहा है कब्जा, नगर निगम बना हुआ है अंजान

वसुंधरा : वसुंधरा सेक्टर–10ए के सामने कुछ लोग ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर रहे है। कब्जाधारियों ने ग्रीन बेल्ट में इंटरलॉकिंग टाइल्स व मिट्टी तक डलवा दी है। वे यहां पार्किंग बना रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम सो रहा है तभी तो लोग ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर रहे है। वसुंधरा सेक्टर–10ए स्थित नित्या होम्स डेवलपर्स के सामने लिंक रोड किनारे ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। इसकी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाती हैं। लेकिन नगर निगम पिछले कई साल से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस कारण लोग ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर रहे है। शुक्रवार को भी कुछ लोगों ने सेक्टर–10ए के प्लाट नंबर–9 के सामने ग्रीन बेल्ट पर मिट्टी व इंटरलॉकिंग टाइल्स डलवा दी और पार्किंग के

लिए कब्जा कर रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम कुभकरण की नींद सोया हुआ है। लिंक रोड किनारे बनी ग्रीन बेल्ट पर लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे है। यहां कब्जा कराने में नगर निगम कर्मचारियों का भी हाथ है।

फिर शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष

गाजियाबाद : स्वास्थ्य विभाग ने मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 2 मार्च से मिशन इंद्र धनुष अभियान–2 शुरू होगा। बुधवार और शनिवार को छोड़कर सात कार्य दिवसों में 2191 गर्भवती और 11366 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण के लिए लक्षित बच्चों में दो वर्ष तक के टीकाकरण से छूटे और ड्रॉप आउट टीकाकरण बीच में छोडने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनके गुप्ता एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एसीएमओ डा. विश्राम सिंह ने मंगलवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की मदद से सूची तैयार कर ली है, जिनका टीकाकरण होना है। उसी के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। बताया गया है कि तमाम बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे टीकाकरण का लोग लाभ उठाएं। मिशन इंद्र धनुष के तहत टीकाकरण का चौथा चरण 2 से 10 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया टीकाकरण का प्रतिरोध करने वाले क्षेत्रों जैसे नटों का मोहल्ला और भोपुरा की इकबाल कालोनी में टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन की मदद ली जाएगी। इसके अलावा धर्म गुरुओं का सहारा लेकर भी लोगों में फैली भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

सीए ने सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर

गाजियाबाद : नोएडा के बर्खास्त आयकर आयुक्त के मामले में आरोपित सीए ने मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपित सीए राजनगर निवासी अनिल कुमार हैं। सीबीआई ने हाल में ही पूर्व आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव के मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार के आरोपित पूर्व आयुक्त संजय श्रीवास्तव के सीए अनिल कुमार का नाम भी शामिल है। आरोप पत्र में सीए अनिल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने अनिल के खिलाफ हाजिर होने का वारंट जारी किया था।

प्लान बदला, इंदिरापुरम एक्सटेंशन के नाम से नहीं बसेगी कॉलोनी

गाजियाबाद : जीडीए इंदिरापुरम एक्सटेंशन नाम से कॉलोनी नहीं बसाएगा। महीउद्दीन कनावनी गांव की जमीन पर नया विकास इंदिरापुरम आवासीय योजना के अंतर्गत ही किया जाएगा। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने मंगलवार को बताया कि पर्याप्त जमीन की व्यवस्था न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया गांव की अधिग्रहित भूमि पर अब तक तीन ग्रुप हाउड्क्षसग के बड़े भूखंड नियोजित किए गए हैं। उनको शनिवार को नीलाम किया जाएगा। यह जानकारी भी दी कि ग्रुप हाउसिंग के भूखंड की कीमत 99750 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। वर्ष 2005 में इंदिरापुरम एक्स्टेंशन कॉलोनी बसाने के लिए ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया था। मूल योजना के तहत इस कॉलोनी को 229.54 एकड़ में बसाना था। मुआवजे को लेकर किसानों से चले विवाद के कारण जीडीए पूरी जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाया। मात्र 60 एकड़ भूमि ही मुआवजा देकर कब्जे में ली जा सकी। ले–आउट तैयार करने पर सड़क, नाले और सीवर लाइन की जगह निकालने के बाद करीब 40 एकड़ भूमि की जीडीए के पास बची। इसमें भी बीच–बीच में कई जगह किसानों की कब्जे वाली जमीन है।

टैक्स जमा नहीं करने पर चार संपत्ति सील

गाजियाबाद : टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम ने शनिवार को चार बकाएदारों की संपत्ति सील कर दी। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब भी टैक्स जमा नहीं होता तो इन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि समस्त जोनल प्रभारियों, टैक्स अधीक्षक व राजस्व निरीक्षक द्वारा टैक्स वसूली का अभियान चलाया गया। कविनगर, वसुंधरा, मोहन नगर व सिटी जोन में एक–एक बकायदारों की संपत्ति को सील कर दिया गया। इन पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है। बता दें निगम के टैक्स विभाग ने 1500 बड़े टैक्स बकाएदारों को चिह्नित किया है।

मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर में अंग्रेजी में काम नहीं कर पा रहे जीडीए कर्मी

गाजियाबाद : ऑनलाइन बिल्डिंग मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर में हिंदी में कार्य करने का प्रावधान किए जाने की मांग शासन से की गई है। जीडीए ने आवास विभाग को सॉफ्टवेयर में संशोधन के लिए इस समेत 15 सुझाव भेजे हैं। जीडीए अधिकारियों का कहना है प्राधिकरण के बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना नहीं जानते। फाइलों पर हो रही नोटिंग भी हिंदी में है। ऐसे में सॉफ्टवेयर पर अंग्रेजी में काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। पांच महीने से भवनों के नक्शे ऑनलाइन बिल्डिंग मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर से स्वीकृत हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर फीड हुए बायलॉज पर नक्शे को परखता है। फिर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। जीडीए में समस्या सामने आई है कि कई सही नक्शे अस्वीकृत कर दिए गए और गलत नक्शों को स्वीकृत दे दी गई। पड़ताल करने पर मालूम हुआ सॉफ्टवेयर में बायलॉज के कई हिस्से फीड नहीं किए गए हैं। जिस वजह से समस्या आ रही है। यह सॉफ्टवेयर केवल अंग्रेजी भाषा को समझता है। ऐसे में जीडीए के नियोजन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के सामने अंग्रेजी भाषा का पेंच फंस रहा है। इस वजह से जीडीए के चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर (सीएटीपी) आशीष शिवपुरी ने आवास विभाग को सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए 15 सुझाव भेजे हैं। उसमें हिंदी भाषा में कार्य का प्रावधान कराने की मांग की है। आवास विभाग को भेजे गए सुझावों में बताया है कि एकल यूनिट के नक्शे में एक से ज्यादा किचिन दर्शाने पर भी सॉफ्टवेयर नक्शा स्वीकृत कर रहा है। इस खामी को दूर कराने के लिए कहा गया है। कॉर्नर के भूखंड पर साइड सेटबैक का प्रावधान सॉफ्टवेयर में कराने का सुझाव दिया है। हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 65 प्रतिशत भूमि पर निर्माण की इजाजत है, लेकिन मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर में इसका समावेश नहीं किया गया है। इस प्रावधान का समावेश करने के लिए कहा गया है। जीडीए के सीएटीपी ने आवास विभाग को बताया है कि साफ्टवेयर से कई ऐसे नक्शे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें भूखंड संख्या, स्थान और भू–स्वामी का नाम समेत कई अन्य विवरण नहीं आ रहे हैं। इस खामी को दूर करने की गुजारिश की गई है।

प्लास्टिक का उपयोग कर बनाई गई सड़क

गाजियाबाद : नगर निगम ने मंगलवार को कविनगर में प्लास्टिक का उपयोग कर 500 मीटर सड़क का निर्माण किया गया। इस तरह से बनने वाली यह शहर की पांचवीं सड़क होगी। इससे पहले कविनगर, संजयनगर, पुलिस लाइन और लोहियानगर प्लास्टिक का उपयोग कर सड़क बनाई जा चुकी है। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने पूजन के बाद सड़क निर्माण कार्य का शुभरंभ किया। बजे कविनगर जोन स्थित वार्ड संख्या–91 में केके–1 से केडी–1 तक जब्त की गयी प्रतिबंधित प्लास्टिक वेस्ट सामग्री का उपयोग करते हुए रूपये 14.33 लाख की लागत से 500 मीटर की सडक निर्माण कार्य किया गया।

15 पुलिया और 17 अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में

गाजियाबाद : दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे के यूपी गेट से डासना तक के हिस्से का काम अब दिन–रात तेजी से चल रहा है। 15 पुलिया और 17 अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में है। तीन मुख्य अंडरपासों में से वेब सिटी का अंडरपास वाहनों के लिए चालू हो गया है। हालांकि पब्लिक ने खुद ही इसे चालू किया है लेकिन काम पूरा हो गया है। इसके अलावा महरौली के दो और बम्हैटा का एक अंडर पास भी पूरा हो गया है। बम्हैटा के अंडरपास से भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसकी सड़क थोड़ी अपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में अतिरिक्त लेबर लगाई गई है।

दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे

प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नामित नोडल अधिकारी सीईओ ग्रेटर नोएडा नरेंद्र भूषण ने भी इस चरण की प्रगति रिपोर्ट मंगवाई है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चौयरमेन के अलावा स्थानीय अफसर अब हर सप्ताह साइट पर जाकर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहें है। दूसरे के साथ ही चौथे चरण के कार्यों की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनेटिरिंग की जा रही है। दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे के दूसरे चरण का काम 70 फीसदी पूरा हो गया है। अब केवल तीस फीसदी कार्य बचा हुआ है।

पॉलीथिन पकडने को बनेगा चेकपोस्ट

गाजियाबाद : दिल्ली से आने वाली प्रतिबंधित पॉलीथिन को पकडने के लिए अपसरा के पास नगर निगम चेकपोस्ट बनाएगा। निगम के कर्मचारी पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद में आने वाली पॉलीथिन को पकड़ेंगे। इससे शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाने में मदद मिलेगा। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बताया कि नगर निगम की टीम शहर को पूरी तरह पॉलीथिन मुक्त बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पॉलीथिन प्रयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लगातार पॉलीथिन जब्त की जा रही है। मगर इसके बावजूद भी शहर में पॉलीथिन की आपूर्ति हो रही है। संभवत दिल्ली की तरफ से वाहनों में शहर में पॉलीथिन आ रही है।

मुतवल्ली ने बेच दी करोड़ो रूपये की वक्फ की संपत्ति

गाजियाबाद : रमतेराम रोड और बजरिया इलाके में करोड़ों रुपये की वक्फ की संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुतवल्ली ने वक्फ की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर दी। आरोपित ने जुलाई 2019 में बजरिया में दो भूखंडों का फर्जी तरीके से पट्टा भी कर दिया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सोमवार को एसएसपी को पत्र लिखकर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डा. अमृता ड्क्षसह ने बताया कि रमतेराम रोड, बजरिया और घंटाघर इलाके में वक्फ की अरबों रुपये की संपत्ति है। यह इस्मालिया वक्फ संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड में वक्फ नंबर 209 ईएक्स द्वितीय में अंकित है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सलीम निवासी रमतेराम रोड को साल 2003 में इस संपत्ति का मुतवल्ली बनाया था। इसने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर वक्फ की संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। जानकारी होने पर बोर्ड ने सलीम को 2013 में मुतवल्ली के पद से हटा दिया। इसके बाद आरोपित को भतीजे को मुतवल्ली बना दिया गया। मुतवल्ली के पद से हटाए जाने बाद भी सलीम फर्जी तरीके से वक्फ की संपत्ति को बेचता रहा। वहीं मुतवल्ली ने इसे साजिश का हिस्सा बताया।

संपत्तियों को फ्री होल्ड करने पर जीडीए की रोक लगाने की तैयारी

गाजियाबाद : अवैध निर्माण रोकने के लिए जीडीए ने संपत्तियों को फ्री–होल्ड करने पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव बना लिया गया है। बोर्ड सदस्यों की सहमति लेकर इसे शासन को भेज दिया जाएगा। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि रोक लगाने पर फैसला शासन ही ले सकता है। वर्ष 1995 में लीज की जमीन और एकल यूनिट मकानों को फ्री–होल्ड करने का शासनादेश आया था। उसमें भूखंड और मकान की मूल कीमत का 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क लेने का प्रावधान किया गया था। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो भूखंड और मकान रियायती दरों पर दिए गए हैं, उनको फ्री–होल्ड नहीं किया जा सकता। इस शासनादेश के आधार पर जीडीए ने 1.40 लाख संपत्तियों में से 60 फीसद को फ्री–होल्ड कर दिया। देखने में आया लीज संपत्ति पर अवैध निर्माण नहीं हुआ, जबकि फ्री–होल्ड संपत्तियों पर नक्शे से हटकर निर्माण कर लिया गया। जीडीए के संपत्ति अनुभाग के अधिकारियों ने वीसी कंचन वर्मा को सुझाव दिया कि संपत्तियों को फ्री–होल्ड करने पर रोक लगा दी जाए तो अवैध निर्माण होने से रोके जा सकते हैं। उनकी सहमति मिलने पर जीडीए के संपत्ति अनुभाग ने फ्री–होल्ड पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है।

वाणिज्य कर विभाग ने मनाया स्थापना दिवस

गाजियाबाद : वाणिज्य कर विभाग ने बुधवार को 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विभाग की और से व्यापारियों, अधिवक्ता ओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समय पर टैक्स देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया गया। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड– 1 अरविंद कुमार और तरसेम लाल के गीतों ने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में जीएसटी पंजीयन कैम्प भी लगाया गया। कार्यक्रम में आए व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के फायदों से परिचित कराया गया।

जीडीए का आठ हजार डिफाल्टरों पर 4.65 अरब से अधिक बकाया

गाजियाबाद : जीडीए ने ओटीएस स्कीम के लिए डिफॉल्टरों की सूची तैयार की है, जिसमें आठ हजार से अधिक डिफाल्टरों पर प्राधिकरण का करीब 4.65 अरब रुपया बकाया है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है। इसमें सर्वाधिक तीन हजार से अधिक डिफाल्टर नंदग्राम के हैं, जबकि सबसे कम एक कोयल एन्क्लेव का है। जीडीए ने कई वर्षों से विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत लोगों पर कई अरब की संपत्ति का बकाया है। प्राधिकरण ने डिफाल्टरों से वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) आरंभ की है। इसके तहत शासन को करीब दो दर्जन आवासीय योजनाओं में डिफाल्टरों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है। सर्वाधिक 3061 डिफाल्टर नंदग्राम के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तुलसी निकेतन में 1697 एवं तीसरे नंबर पर 1624 डिफाल्टर इंदिरापुरम के हैं। इनमें सर्वाधिक 190 करोड़ रुपये से अधिक इंदिरापुरम के डिफाल्टरों पर है। इसके अलावा बाल्मिकी कुंज, इंदिरा कुंज, उदय नगर, वैशाली, संजय नगर, मधुबन बापूधाम, प्रताप विहार, स्वर्ण जयंती पुरम, तुलसी निकेतन, कौशांबी, इंद्रप्रस्थ, शास्त्री नगर, यूपी बार्डर चिकमपुर आदि के 8294 डिफाल्टर शामिल हैं।

काट दी सीएचसी की बिजली, 20 घंटे बाद दोबारा शुरु की गई बिजली सप्लाई

गाजियाबाद : बिजली का बिल बकाया होने पर विद्युत निगम ने डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का कनेक्शन सोमवार शाम को काट दिया। बिजली गुल होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार दोपहर बाद सीएमओ की ओर से की गई शिकायत के बाद सीएचसी का कनेक्शन जोड़ा गया। रात भर सीएचसी अंधेरे में डूबी रही और सुबह जनरेटर के जरिए ऑपरेशन किए जा सके। डासना सीएचसी पर दो महीने का लगभग चार लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। सीएचसी प्रभारी के अनुसार सोमवार शाम सात बजे बिजली कट गई। जिसके चलते रात भर सीएचसी पर अंधेरा रहा।

पत्रकार एसोसिएशन का होली मिलन कार्यक्रम 8 मार्च को

गाजियाबाद : गत वर्ष की भांति इस बार भी पत्रकार एसोसिएशन गाजियाबाद होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 8 मार्च दिन रविवार को आयोजित होगा। इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यगणों ने अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद बैठक में पत्रकारों के हित से जुड़ी अन्य कई बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें सभी उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यगणों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में एसोसिएशन से जुड़े सभी पत्रकारों के हितार्थ हेतु फंड एकत्रित करने पर भी विचार–विमर्श किया गया। आयोजित की गई बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय जैन, योगेश कौशिक, संदीप सिंघल, डा.धीरज भार्गव, तोषिक कर्दम, आशित त्यागी, संजीव वर्मा, रेखा अग्रवाल, सी.एन. राही, सोबरन सिंह, अजय रावत, मुकेश गुप्ता, सुनील शर्मा, अशोक कुमार, नरेश राजपूत, किशन स्वरूप, रवि तुषार, मनीष गुप्ता, सुधीर रस्तौगी, जावेद खान, आशीष रघुवंशी, मुकेश कर्दम, शिवम गिरी, मनोज शर्मा, दिनेश गौड़, राशिद अली, वीरेंद्र सिंह, प्रशांत कुमार आदि दर्जनों पत्रकार मौजूद थे।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 1221 परीक्षार्थियों ने छोड़ दी बोर्ड की परीक्षा

गाजियाबाद : यूपी बोर्ड की बुधवार को पहली पाली में हाईस्कूल की सिलाई विषय की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली में हाईस्कूल की वाणिज्य और इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। किसी भी केंद्र पर नकल का मामला नहीं मिला। हाईस्कूल की वाणिज्य की परीक्षा के लिए कुल 1889 छात्र–छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 1810 ने परीक्षा दी जबकि 79 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा के लिए कुल 23070 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 21928 ने परीक्षा दी।

कैंप लगाकर और लाउड स्पीकर पर दी ओटीएस की जानकारी

गाजियाबाद : जीडीए ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की जानकारी देने के लिए मंगलवार को कई कॉलोनियों में कैंप लगाए। लाउड स्पीकर पर गली–गली प्रचार किया गया और पर्चे बांटे। रिकॉर्ड में लिखे बकाएदारों के पते से नोटिस वापस लौटने के कारण जीडीए को यह कदम उठाना पड़ रहा है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि इस प्रयास के बाद कोई बकाएदार यह नहीं कह पाएगा कि उन्हें इस योजना की सूचना नहीं दी गई। जीडीए ने राजेंद्रनगर, इंदिरापुरम, संजयनगर, स्वर्णजयंतीपुरम, गोविंदपुरम समेत कई कॉलोनियों में कैंप लगाकर बकाएदारों को ओटीएस योजना की जानकारी दी। बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने पर बकाया राशि में जुड़ा पैनलटी ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा दो फीसद की छूट दी जाएगी। बताया कि 50 लाख रुपये तक एक तिहाई बकाया राशि का भुगतान मांग पर तत्काल करना होगा और बाकी राशि का भुगतान तीन किस्तों में करने का मौका दिया जाएगा। 50 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि पर भुगतान के लिए छह किस्तें बनाई जाएंगी। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि करीब 7600 छोटे–बड़े बकाएदारों पर 800 करोड़ रुपये बकाया है। ओटीएस की छूट के बाद इनसे 400 से 500 करोड़ रुपये के बीच आय होने की उम्मीद है।

कागज की गड्डी थमाकर 32 हजार ठगे

साहिबाबाद : शालीमार गार्डन में दो लाख रुपये का झांसा देकर ठगों ने एक व्यक्ति से 32 हजार रुपये ठग लिए। ठग पीडित को कागज की गड्डी थमाकर 32 हजार रुपये ठगे। पीडित ने साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडित प्राणजीत कुमार गणेशपुरी शालीमार गार्डन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह सोमवार को शालीमार गार्डन के एक बैंक से 32 हजार रुपये निकालने गए थे। वह रुपये रुपये लेकर बैंक से बाहर आ रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे 2000 खुले मांगे। उन्होंने खुले रुपये दे दिए। व्यक्ति ने प्राणजीत से कहा कि वह चार लाख रुपये चोरी करके लाया है। इसको लेकर ठगी की।

दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे से जुड़ेगा सिद्धार्थ विहार

साहिबाबाद : सिद्धार्थ विहार और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लाखों लोगों का सफर जल्द ही आसान होने जा रहा है। आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार की 50 मीटर रोड का टेंडर जारी कर दिया है। जल्द ही सिद्धार्थ विहार की मुख्य सड़क का निर्माण शुरू कर इसे दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा। इस रोड से वाहनचालक आसानी से दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर सकेंगे। वहीं यू टर्न लेकर आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना को 50 मीटर रोड दो हिस्सों में बांटती है। इस रोड के एक ओर सेक्टर एक, तीन, पांच, सात और नौ हैं तो दूसरी ओर सेक्टर दो, चार, छह, आठ दस हैं। यह 50 मीटर रोड लंबे समय से खस्ताहाल थी। अब आवास विकास परिषद ने करीब सवा दो करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण शुरु करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। यह रोड एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड से जुड़ेगी। अभी तक यह रोड सिद्धार्थ विहार योजना के अंदर ही बनी है। खस्ताहाल भी है। इसे अब एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दिल्ली से आने वाले वाहनचालक सीधे सिद्धार्थ विहार में एंट्री कर सकेंगे।

EDITORIAL

Keep up the pressure: decision by FATF on Pakistan

The decision by global watchdog, the Financial Action Task Force (FATF), at its plenary in Paris last week, to keep Pakistan on its "greylist" for monitoring its record against terror financing was no surprise. While the Pakistan government has yet to complete the 27-point action plan it was given in June 2018, it has, according to the FATF, made some progress. As a result, the 39-member group that includes India decided to extend Pakistan's September 2019 deadline until June 2020. Actions Pakistan still needs to carry out include tightening security and banking restrictions to block loopholes through which designated groups including the Taliban, al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammad access funding. It also calls on Pakistan to begin prosecutions against terrorists and sanction entities that are flouting the UNSC's rules for designated terror organisations. The FATF Chairman's final comment says Pakistan must comply with all 27-action points — it has cleared about 14 — in the next four months or face financial strictures by being placed on the "blacklist". Pakistan is one of 18 countries on the greylist; Iran and North Korea are on the blacklist.

The FATF's sharp language is significant, yet according to the force's consensus rules, Pakistan believes it might be able to slip through the deadlines if it is able to ensure that three countries, China, Turkey and Malaysia, which have pledged support, veto any move to blacklist it. Pakistan also appears to have benefited from playing a role in U.S.-Taliban talks as it seems the U.S. and its allies are not enforcing the deadline to complete the action plan as before. A senior U.S. official's statement in January welcoming Pakistan's progress in its FATF commitments may have set the stage for the final plenary decision. While the FATF's Chairman's wording was strong, it was a repetition of the threat he served Pakistan last year, and there is a danger that Pakistan, a country that has not sustained punitive action against thousands of designated terrorists and entities, will feel immunity from the process. The Pakistani court's hurried conviction of LeT chief Hafiz Saeed on terror financing charges just before the Paris meet appeared to be a command performance, and its shocking submission to the FATF that it cannot trace Masood Azhar must be scrutinised further by the international body. Among other issues on the agenda during U.S. President Trump's India visit, it is necessary that India raises the need to continue to hold Pakistan to account on terror, and not flag in attention just when the FATF process has begun to extract results from Islamabad.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Noida Sector 18 traders demand control room to monitor CCTVs

NOIDA: In the aftermath of the Sector 12 jewellery showroom robbery, traders of Sector 18 market have offered to install 60 CCTV cameras in the area and demanded space to set up a control room for monitoring the cams for continuous surveillance. Sushil Kumar Jain, president of Sector 18 market association, said they had provided some 65 CCTV cameras around three years back but most of them were dysfunctional as the wires have either been stolen or cut and due to lack of maintenance. "For continuous monitoring, it is best that one of our operators too sits in the control room. We will also get five gunmen for the market.

Ghaziabad stamps department to recover duty on extra FAR

GHAZIABAD: Keen to shore up revenues, the district stamps and registration department plans to recover from developers stamp duty pending on additional floor area ratio (FAR) purchased from the Ghaziabad Development Authority (GDA). Citing a government order, the department has sought from GDA details of all such developers who bought extra FAR in the past five years, officials said. The state government, for the current fiscal, has set a target of Rs 16.74 crore as stamp duty, and the Ghaziabad stamps and registration department has so far met 85% of the target. If stamp duty on additional FAR is recovered from developers, officials believe it would help the department meet its annual revenue target. AIG (stamps) KK Mishra told TBC that there's a provision to pay stamp duty on additional FAR as per a 2015 government order (GO). "But the GO was never implemented as a group of 28 builders had in 2016 moved the Allahabad HC against it and secured a stay," he said. "However, we have now received fresh orders from the government for implementing the GO and so we have sought details from GDA of developers who availed purchasable FAR so that we could issue notices to them for recovery of pending stamp duty," added Mishra. The department, in the meantime, has referred the matter to the standing council over the status of the case that was filed by a consortium of builders. The GDA normally allows 2.5 FAR, but a developer can seek up to 3.75 FAR from the development authority at an additional cost. which is 60% of the land cost in case of commercial property and 40% in case of group housing societies.

Fake Aadhaar, PAN cards used for duping banks, 2 held

NOIDA: Two men, accused of duping banks of crores of rupees using credit cards made on the basis of forged Aadhaar and PAN cards, have been arrested from Greater Noida by the Uttar Pradesh police, officials said on Wednesday. The Special Task Force (STF) of the state police also recovered electronic data of 25,000 citizens which includes their phone numbers, Aadhaar and PAN details along with a separate list of Aadhaar and PAN details of another 6,000 people from the duo, officials said. The officer said the duo was arrested and jailed in 2013 over a fraud case in which they had duped a personal assistant of the then Chhattisgarh chief minister.

Three-day flower show inaugurated at Ramlila Ground in Noida

NOIDA: The CEO of Noida Authority, Ritu Maheshwari inaugurated the 34th edition of the popular annual Noida flower show at the Ramlila Ground in Sector 21A on Friday. The show is held every year by the Authority in collaboration with the Floriculture Society of Noida. Visitors to the annual flower show took to social media to post photographs of the flowers on display. The show will last from February 21-23. The theme for this year's show is Dianthus. Over 3,500 species of flowers and plants will be showcased in the show. Commenting on the show, Authority CEO, Ritu Maheshwari said, "The focus of the show is to highlight the air-purifying plants and say no to plastic. The emphasis this year is on reducing waste and need for recycling and grow plants." Visitors quickly took to social media to start posting pictures of the wide range of flowers at the show. The Instagram hashtag #noidaflowershow has been used widely by people while posting pictures. As part of the three-day event, there will be a kiosk to give plants in exchange for plastic which will be organised by Human Touch Organisation. Nukkad Nataks are also being staged on the same topic. Schools like Delhi Public School are also participating in the show. A promotional stall for the upcoming Jewar airport has also been put up.

CP-like plan to end car chaos in Noida's Sector 18 market

NOIDA: The congested Sector 18 market area will soon have marked spots to tell visitors where they can park their vehicles and where they can't. The Noida Authority CEO on Tuesday asked officials to finish a survey soon and create designated spots for parking of vehicles. Officials said the entire market area was being surveyed to mark zones where vehicles would be allowed and areas that can be accessed only on foot, such as the Tikona Park. These parking spaces would be in addition to the multilevel car park that has direct access to the market area. Despite the multilevel parking facility, people tend to park their vehicles haphazardly along shops they intend to visit. Last year, the authority and traffic police had proposed turning the entire Sector 18 market area vehicle-free, but the plan had met with resistance from traders and shopkowners. They claimed it would reduce crowd and slow down business. "Steps are being taken to reduce congestion and create pedestrian-friendly zones, where people can walk and enjoy with their families. We may also introduce some new activities soon. The entire area may be like Connaught Place, where vehicles are not allowed in certain parts," said Rajeev Tyagi, general manager of the Noida Authority. The Authority is also set to float by March tenders for some of its major infrastructure projects, such as the city's second golf course and habitat centre in Sector 151A, Parthala Chowk flyover and a skywalk between Botanical Garden metro station and the Sector 18 market. The CEO on Tuesday reviewed the progress and asked officials to expedite work. A blueprint to decongest the Master Plan 1 road is also expected to be finalised soon as RITES is likely to submit its survey report. Traffic police had prepared a report and given it to the authority about 15 days ago.

Want driving licence? You may have to watch traffic film first

GHAZIABAD: The district administration has asked transport department officials to prepare a film on traffic rules that can be shown to new applicants and those whose licences have been suspended or confiscated for violating road safety norms. The administration is planning to tie up with theatres across the district so that the film can be shown between 9.30 am and 10.30 pm. Till then, a projector will be set up at the RTO where the film can be shown. "The system will be in place in the next 15 days," said assistant regional transport officer (enforcement) Rajesh Singh. DM Ajay Shankar Pandey said, "A violator will now have to show proof that she/he has seen the film and complete all other formalities, like filing an affidavit, before a decision on restoration of licence can be taken." "Licence can be suspended for four offences — speeding, overloading, jumping red lights and drunk driving. It can be suspended for one month to six months for these offences. The transport department has been asked to seek legal advice regarding adding this new condition of watching a film based on traffic rules.

Noida's power infrastructure upgrade by March?

NOIDA: The ongoing power infrastructure upgrade work is set to enhance transmission capacity in Noida and Greater Noida by 80%, officials said. Last year, the peak summer demand was 1,400 mW in the twin cities. Once the work is complete, Uttar Pradesh Power Transmission Limited (UPPTL) will be ready with 2,400 mW capacity transmission facilities, officials said. "I have told PVVNL officials that they should complete construction of 33 kV lines and 33/11 kV substations by March 31.

Bodies of two youths found in Bulandshahr region

MEERUT: Twenty days after a tragic accident in which an SUV fell into Upper Ganga Canal in Muradnagar region of Ghaziabad, bodies of two missing youths, including a girl, have now been found 48 km away from the site of accident in Sikandrabad town of Bulandshahr. The incident had occurred on the night of February 1 when an SUV carrying six students, all in their early 20s, fell into a canal near Muradnagar. While two of them swam to safety, four others remained missing. Despite all attempts, they could not be traced. Two bodies were recovered eight days after the incident. But, two others were still missing. Now the bodies of two of the missing youths have been found and identified through the documents on them. The bodies are said to be in decomposed state. The girl, identified as Kanika, belonged to Dehradun while the other youth, Himanshu, was from Muzaffarnagar. Himanshu's father Sukhbir Singh said, "My son Himanshu along with his friends Nishant, Anmol, Srishti, Kanika and Harshit were travelling from Dehradun to Delhi.

Woman's body stuffed in sack found in Greater Noida

NOIDA: An unidentified woman's body was found stuffed in a sack in Greater Noida on Thursday, with police suspecting that she was killed elsewhere and later dumped in Gautam Buddh Nagar, officials said. The body was found in the bushes along the Yamuna Expressway near Murshadpur under the Dankaur police station limits, they said. "The body was found wrapped in a blanket and stuffed inside a plastic sack. The victim appears to be around 45-50 years of age. Prima facie, it looks like she was killed elsewhere and her body was disposed here," a police official said.

This January, street crimes down by 30%

GHAZIABAD: Believe it or not, street crime numbers in Ghaziabad have gone down by almost 30% in the first month of this year compared to the corresponding period last year. According to latest data shared by Ghaziabad police, 12 cases of snatching - including jewellery, mobile phones and purses - were reported in January 2020 compared to 19 in January last year. Similarly, the number of thefts have also come down from 29 last year to 11 this year. Cases of vehicle thefts have also decreased in the first month of this year, with 221 reported as compared to last January's figure of 293. Cases of loot though saw a rise, with nine cases registered this year over three last year, as per the police data. Ghaziabad police have attributed the decline in crime rate to the launch of Tejas, a patrolling unit comprising 16 policemen in plainclothes, in October last year. "This has helped in curbing street crimes to a large extent as police officials, including women cops, are now patrolling public places without uniforms. Over 50 criminals have been arrested by this unit and soon the strength of the force will be extended," a senior police officer said. However, residents argue that these crime numbers do not necessarily reflect the trends as many incidents go unreported. Rohit Verma, a resident of Amrapali Village in Indirapuram, said he had to run from pillar to post to get an FIR registered after his car was stolen near the Habitat Centre. "The car was lifted by criminals on January 9 and the FIR was registered a week later only after I met the SSP," he said. Ghaziabad SSP Kalanidhi Naithani, however, said that they were pursuing "a cop after every criminal" policy to curb crimes in the district. "Over a thousand active criminals have been identified by police. We will soon nab all of them," he added.

Greater Noida's choked drains to be cleaned by May?

Noida: Greater Noida's issues of sewer blockages and missing manholes are set to be resolved by May, in keeping with deadlines set by officials. Sewer lines have already been cleaned and connected with the main network in areas such as Sectors Pi 3, Delta 1 and Knowledge Park. However, 13 of the larger residential sectors remain — Alpha 1 and 2, Delta 1, 2 and 3, Beta 1 and 2, Gamma 1 and 2, Eta 1, P-3 area, Swarna Nagari and Sector 36. According to the plan, cleaning in various sectors is happening simultaneously and will take about 15-20 days to complete.

MLA demands 15% quota for Jewar farmers in plot scheme

GREATER NOIDA: For the displaced farmers of six villages that were acquired for the upcoming Jewar airport, MLA Dhirendra Singh has written to the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) demanding a minimum 15% quota in residential, industrial and commercial land/plot schemes of the Authority as well as a relaxation in allotment rates. While the demand is expected to be placed in the YEIDA board meeting on February 28, the Jewar MLA has also asked for land to build a community health centre and a school for the affected families. Notably, land from Ranhera, Dayantpur, Rohi, Kishorepur, Parohi and Banwariwas villages was acquired for the Jewar Airport. "I have written to the YEIDA CEO for a fixed quota for displaced farmers of Jewar airport land in their residential, commercial and industrial plots schemes. I have demanded a 15% quota for these farmers," Dhirendra Singh, Jewar MLA, told TBC. According to Singh, these steps will ensure proper rehabilitation of farmers who lost their means of livelihood due to the airport land acquisition.

Rs 238 crore infrastructure push for Jewar Bangar; roads & hospitals to come up soon

GNOIDA: The area identified to resettle and rehabilitate families displaced due to the Jewar airport project will be developed with an amount of Rs 238 crore, officials said. The money will be utilised to develop infrastructure in Jewar Bangar village that will house 3,627 families. In May last year, the state government had set aside Rs 895 crore for rehabilitation of the affected families. Ranhera is one of the six villages where farmers have parted with their land for the airport project.

Kalindi Kunj border opened fully? Commuters confused

NOIDA: Confusion over whether the Kalindi Kunj border has been opened for vehicles led a number of commuters from the Noida side to flock to the spot, only to be redirected to the DND route that they have been taking for more than two months now. As of now, Delhi Police has opened only one carriageway at the border — the one from Faridabad to Noida. But commuters said a few TV channels apparently flashed news that both sides of the road had been opened for vehicles, leading to the confusion. On Sunday morning, there was a long tail of vehicles outside Okhla Bird Sanctuary metro station, where barricades have been placed. Traffic police officers said things could have much worse had it been a weekday. "As of now, we are only allowing two-wheelers to cross the barricades," a policeman said. Noida traffic police clarified that only the carriageway from Faridabad to Noida had been opened by their Delhi counterparts and they did not have any directive to remove barricades on the other side. "We had closed the road on the Delhi Police's directions. It will not be opened until they ask for it," said Anil Kumar Jha, the additional DCP (traffic).

No ambulance, woman delivers in police van

GHAZIABAD: Facing a cash crunch, the Ghaziabad Development Authority (GDA) has meticulously worked out a funding pattern of two proposed metro corridors — Noida Electronic City to Sahibabad and Vaishali to Mohan Nagar — on its own and in a manner that the burden is proportionately shared by all stakeholders. The proposal will be put up by GDA vice chairperson Kanchan Verma before the state government in Lucknow on Thursday. "From the very onset, we have been saying at all platforms that the funding pattern adopted in Dilshad Garden to New Bus Adda metro corridor, in which GDA had to bear the major cost, will not work as our financial status is not good," Verma told TBC. "Even the Delhi Metro Rail Corporation, which had recently submitted detailed project reports for the two metro corridors, suggested that the UP government through its agencies bear the major cost, which means the major cost burden will fall GDA. So we have tweaked the funding pattern," she added. In fact, for the Noida Electronic City to Sahibabad corridor, GDA has proposed that the UP government should alone contribute Rs 758 crore of the total estimated cost of Rs 1,517 crore. And the remaining be borne by its other agencies — GDA Rs 152 crore, GMC Rs 55 crore, the UP Housing Board Rs 97 crore and UPSIDC Rs 19 crore. Similarly, for Vaishali to Mohan Nagar corridor, the UP Government's share as suggested by GDA is Rs 904 crore out of the total estimated cost of Rs 1,808 crore, while GDA's share have been computed to Rs 229 crore, GMC Rs 82 crore, the UP Housing Board Rs 146 crore and UPSIDC Rs 29 crore. "This way the cost would be proportionately shared by the UP Government, GDA, GMC, the UP Housing Board and UPSIDC. This is doable. We have also suggested that DMRC too contribute in the form of rolling stocks, in the two projects, which it had conveniently omitted in the detailed project reports," said another official. "If the state government agrees to the funding pattern suggested by GDA, it will be a win-win for us. We are going to lobby hard on Thursday's meeting for our proposals," the official added. The Vaishali-Mohan Nagar metro corridor has been estimated to have a daily ridership of 37,000 while it's expected to be 30,000 for the Electronic City-Sahibabad corridor.

GDA chalks out funding pattern for 2 metro corridors

GHAZIABAD: Facing a cash crunch, the Ghaziabad Development Authority (GDA) has meticulously worked out a funding pattern of two proposed metro corridors — Noida Electronic City to Sahibabad and Vaishali to Mohan Nagar — on its own and in a manner that the burden is proportionately shared by all stakeholders. The proposal will be put up by GDA vice chairperson Kanchan Verma before the state government in Lucknow on Thursday. "From the very onset, we have been saying at all platforms that the funding pattern adopted in Dilshad Garden to New Bus Adda metro corridor, in which GDA had to bear the major cost, will not work as our financial status is not good," Verma told TBC. "Even the Delhi Metro Rail Corporation, which had recently submitted detailed project reports for the two metro corridors, suggested that the UP government through its agencies bear the major cost, which means the major cost burden will fall GDA. So we have tweaked the funding pattern," she added. In fact, for the Noida Electronic City to Sahibabad corridor, GDA has proposed that the UP government should alone contribute Rs 758 crore of the total estimated cost of Rs 1,517 crore.

500 fudged income for PMAY grants?

GHAZIABAD: About 500 beneficiaries fudged details of their income certificates to fraudulently avail grants worth at least Rs 2.5 crore under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), according to sources in the nodal agency authorised to release the funds for constructing the dwelling units. P K Sharma, project officer, District Urban Development Agency (DUDA), said they are in the process of assessing the number of such beneficiaries and the exact amount. "The amount that went into the wrong hands is still being ascertained. At this point, I can confirm that we received numerous complaints that beneficiaries fudged income certificate details to avail grants under PMAY. After initial investigation, it was found to be true in many cases. We will issue recovery notices to all such beneficiaries," he said. Highly placed sources said that some officials in one of the surveyor agencies hired by DUDA to verify beneficiaries' documents may have been complicit and taken bribes to overlook discrepancies in income certificates. "We had engaged three surveyors, which were entrusted with the responsibility of verifying documents submitted by beneficiaries seeking grants under PMAY," said Sharma.

NGT directs DPCC to submit fresh report on 5,000 illegal e-waste processing units in Delhi-NCR

NEW DELHI: The National Green Tribunal directed the Delhi Pollution Control Committee and UPPCB on Thursday to submit a fresh report on a plea alleging that 5,000 illegal e-waste processing units are operating in and around Delhi. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel ordered that the report be filed by DPCC in coordination with the District Magistrates of East and North East Delhi with regard to the area in Delhi, the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB) and Ghaziabad District Magistrate before April 23. The direction came after perusing a report filed by the DPCC which said that Central Pollution Control Board had convened a meeting of all stakeholders to discuss the findings of the study undertaken by an NGO, Toxics Link, and to discuss ways for stopping unauthorised e-waste recycling units. The pollution monitoring body told the NGT that nine teams were constituted to carry out inspections of the areas falling in different districts to identify illegal e waste storage and handling units for their effective closure. DPCC took action on its own against illegal e-waste handling units in old Seelampur area and closed 57 premises effectively in the month of July 2019, it said. The tribunal, however, asked DPCC to file fresh action report. The NGT had taken note of a news article which said that 5,000 illegal e-waste processing units are operating in and around Delhi as per the Toxic Link study. The hotspots are located in Northeastern and Eastern parts of Delhi, including Seelampur (Shahadra), Mustafabad (North East Delhi), Behta Hazipur and Lone (Ghaziabad). Waste is sold to the said units by dismantlers and recyclers, it said. "Over 5,000 illegal e-waste processing units employing approximately 50,000 people continue to operate in violation of environmental norms in the capital, a study by think tank Toxic Link has revealed. The study has found that these units operate in 15 "informal hotspots" in Delhi. "According to the study titled 'Informal E-waste Recycling in Delhi: Unfolding impact of two years of e-waste (Management) Rules 2016', the hotspots are located in the Northeastern and Eastern part of Delhi, including Seelampur Mustafabad (North East Delhi), Behta Hazipur and Loni (Ghaziabad), among other places," the news article said. It said that Seelampur, Mustafabad, Behta Hazipur and Loni in Ghaziabad account for about 57 per cent, 15 per cent, 9 per cent and 10 per cent of all e-waste informal processing units.

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम – 2824416
आवास – 2820106
एडीएम (सिटी) – 2828411
एडीएम (प्रशासन) – 2827016
सिटी मजिस्ट्रेट – 2827365
आयकर विभाग– 2714144
पासपोर्ट कार्यालय– 2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी –2820758,9643322900
पुलिस अधीक्षक नगर–2854015
पुलिसअधी. यातायात–2829520
सीओ प्रथम– 2733070
सीओ द्वितीय – 2791769
सीओ एलआईयू– 2700925
सीओ लोनी– 3125539

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए – 2791114
जीडीए सचिव – 2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. – 2710754
सी.एम.एस. – 2730038
आपातकालीन – 2850124
कोलम्बिया एशिया –3989896
यशोदा अस्पताल–2750001–04
गणेश अस्पताल –4183900
संतोष अस्पताल –2741777
सर्वोदय अस्पताल –2701694
नरेन्द्र मोहन अस्पताल 2735253
जिला अस्पताल(एम्बुलेंस) 2730038
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

जीएम 2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम – 2734906
कोतवाली – 2732099
जिला कन्ट्रोल रूम –2766898

पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम– –9643322921
एसएचओ खोड़ा– –9643322922
एसएचओ–साहिबाबाद– – 9643322923
एसएचओ लिंक रोड– –9643322924
कोतवाली – 2732088
सिहानी गेट – 2791627
कविनगर – 2711843
विजयनगर – 2740797
इंदिरापुरम – 2902858
लोनी – 2600097
अग्निशमन विभाग –2732099 9818702101
रेलवे इन्कवायरी –131

नगर निगम

नगरायुक्त– 2790425,2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर –2797840, 139
रिजर्वेशन – 8888
रोडवेज इन्कवायरी –2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
Phone No.: 0120-4561000

1.5km road to link Siddharth Vihar and NH-9

GHAZIABAD: The UP Housing Board, which administers Siddharth Vihar, is constructing a 1.5km-long road that will offer the township direct access to NH-9. Being built at a cost of Rs 2.15 crore, the road will be ready in the next six months and is expected to change the fortune of the township, officials said. Though Siddharth Vihar is situated next to NH-9, it has no direct access to the expressway till now. A road — though not fully operational — is there, but it ends 600 metres before the national highway. "We decided to construct the 1.5km-long road as we are developing Siddharth Vihar as a major residential hub in Ghaziabad. The four-lane road will be ready in six months," Narsingh Singh, superintending engineer of UP Housing Board, told TBC. Anticipating that the integration of the under-construction road with NH-9 could be a challenge, Singh said that "we will soon hold a meeting with officials of the National Highways Authority of India (NHAI) and chalk out a plan that will ensure seamless integration with the high-speed corridor". Spread across 635 acres, Siddharth Vihar is developing and expected to cater to over 3 lakh people in the next couple of years.

Man facing business losses shoots self

NOIDA: A 40-year-old man struggling with losses in his transport business allegedly shot himself dead here on Friday, police said. The man, a resident of Behlolpur village, shot himself while in Garhi Chaukhandi village and was rushed to a private hospital in Sector 62 where the doctors declared him dead, the police said. "Information was received at Phase III police station from the hospital as well as the nephew of the deceased about the death due to bullet injury. The man has been identified as Sundar Singh," the deputy commissioner of police, Central Noida, Harish Chander said.

Interstate railway recruitment scam busted

GHAZIABAD: Police claimed to have busted an inter-state fake job racket on Friday, with the arrest of two men who allegedly cheated several youths on pretext of providing them employment in Indian Railways. While those arrested include the kingpin, an MBA graduate named Vikar Ul, five other members of the gang are still at large. Cops said the accused duped some 300 youths to the tune of Rs 5-8cr in the past 10 years on the pretext of jobs for the posts of assistant station master at Rs 20 lakh per candidate and ticket collector at Rs 15 lakh. And for Group C & D posts in the Indian Railways, they would charge Rs 10 lakh per candidate. The scamsters also followed a set procedure similar to one followed by government recruitment agencies. After "recruitment", police said, the accused organised fake training sessions at a rented centre near Bhusawal junction in Maharashtra for the candidates and also made them work at stations in Delhi and Ghaziabad on stipends. They also ran a bogus health centre in Delhi, where they conducted medical tests for up to Rs 1 lakh per candidate.

Gangster held for EPE robberies

GNOIDA: A wanted member of the Randeep Bhati gang was arrested on Thursday for allegedly robbing two truck drivers at gunpoint in the name of "local tax" . Ashok Kumar, from Dabra, and two others, Yatendra Lala and another person, allegedly stopped two trucks on the Eastern Peripheral Expressway on Wednesday. Driver Dharmveer said the incident took place at 10.45am when he and another driver were going to deliver goods in Narela. "We were entering the expressway from Rampur Fatehpur side when three men came in a car and stopped our trucks.

As government drags feet on JJB, 1,170 cases wait to be heard in Noida

NOIDA: In the absence of fully functioning juvenile justice boards (JJBs) in the state, minors held for petty offences that merit no more than four months in detention have been waiting it out in custody as the courts adjourn hearings and the government drags its feet on appointments. "In all, there are about 1,170 cases pertaining to juveniles that remain pending in Gautam Budh Nagar. The Noida observation home alone has 180 children, of which 15 have been lodged for petty offences like theft. They could have been released by now," said former JJB member Aneet Baghel. The terms of JJBs and child welfare committees (CWCs) in the state ended in December 2019, but new ones were not set up by the state government, TBC had reported earlier. A month after they went defunct, the government issued an order saying that a nominated judicial magistrate would take over the work of JJB and an official at the level of an ADM or SDM, nominated by the DM, would function as the CWC. Nirdesh Bhati, a lawyer who is representing two juveniles in theft cases, said that the hold-up under this arrangement is that while a single magistrate can pass orders for release of seized items, warrant rejection or dates for hearings, she or he cannot pass a verdict in the case. Consequently, families of juvenile accused have been queuing up outside observation homes because presiding officers cannot take any decision in absence of social workers. "The two kids, about 14-15 years old, I am representing stand accused of stealing a gold idol from a dhaba. Their parents are labourers and cannot afford sureties for bail. They have been in detention for the past four-five months. The last hearing was in February, when we were told a decision in the case would be taken in the next hearing. That never happened," said Bhati. Another lawyer, Arvind Kumar, said he is handling five cases of juveniles.

Fire inside ATM vestibule in GNoida

NOIDA: A fire broke out inside an ATM vestibule, apparently due to a short circuit, in Greater Noida on Friday burning down cash stocked in the machine, police said. The blaze was reported around 12pm at an HDFC ATM in Tugalpur village, under Knowledge Park police station limits, and was subsequently doused by locals, police and fire department officials, they said. "The fire broke out due to a short circuit inside the ATM vestibule and was doused soon. No person was harmed during the incident," a police spokesperson said. The amount of cash that got charred and other loss to property was being assessed, the official added.

Coronavirus scare: China imports stop, mobile market in Noida feels heat

NOIDA: The disruption of the supply chain due to the coronavirus outbreak in China has impacted the mobile phone market. In Noida, which forms a big market for Chinese phone-makers, traders have been battling a 10-15% slump in sales over the past one week. Market observers fear that at this rate, sales in the city could dip to around 50% as shops will run out of phone accessories. A phone seller in Noida usually stocks goods worth Rs 50 lakh that he hopes to sell over two months. Most traders said their stocks would deplete by next month, and if they are not replenished at the earliest, some may even have to pull down shutters for some time. The fear of massive financial losses has led shop owners to jack up rates. The price of accessories such as phone covers, earphones, battery chargers and other hardware has seen a rise between Rs 300 and Rs 1,500 in the past one week. While a screen guard for any mid-range smartphone would cost Rs 250 earlier, it is now dearer by Rs 100 or more. Similarly, mobile covers or folders have gone up from Rs 600 to Rs 900, and screen displays now cost Rs 1,300 against Rs 1,000 earlier.

Noida-Faridabad road was re-opened briefly for an ambulance: Noida ACP

NOIDA: The Assistant Commissioner of Police, Noida, Arun Kumar Singh on Friday said that the road connecting Faridabad to Noida was re-opened briefly for the passage of an ambulance. Noida-Kalindi Kunj route opened just for few minutes Talking to ANI, he said: "The road was not re-opened. We gave passage to an ambulance and people thought we have re-opened the road. Police duty will be increased to avoid any such confusion." "We have not received any guidelines from authorities and the road continues to remain closed until further orders," he added.

proposed vendor zone: Noida: Sector 34 RWA opposes proposed vendor zone

NOIDA: The sector 34 RWA has opposed the proposed vendor zone in the sector in a meeting with authority officials on Thursday citing already existent four big markets in the sector which fulfil its (sector's) requirements. Further, the residents opposed the location where vendor zone is proposed, which includes the boundary wall of apartments saying it would lead to problems of commuting for the residents. Apart from this residents maintain that the weekly Friday market in the sector also adds to traffic and sanitation mess and that it should be shifted from the sector. "We had a meeting with Mukesh Vaish, senior manager from work circle 5 Noida Authority at our community centre today, where apart from discussion on the construction of inner roads, we also discussed the proposed vendor zone area for the sector. We told them that we already have four big markets in the sector - Amaltash, Jasmine, Maulshree and B-12B market - and there's no need for a vendor zone. But even then if they have to make one, then the proposed location which is near the boundary wall of our apartments as well as entry points of parks etc.

पॉलीटेक्निक का टूटा फर्नीचर देखकर मंत्री ने जताई नाराजगी

गाजियाबाद : प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी ने बुधवार को शास्त्रीनगर स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में गंदगी व फर्नीचर टूटा हुआ मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। शिक्षा मंत्री ने प्रधानाचार्य व संबंधित अधिकारियों को पॉलीटेक्निक की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। प्राविधिक शिक्षा विभाग मंत्री कमल रानी बुधवार को जिले में थीं। इस दौरान उन्होंने औचक रूप से राजकीय पॉलीटेक्निक का निरीक्षण किया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने चार कक्षाओं व दो वर्कशॉप कक्षाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में कूड़ा मिलने, गंदगी होने व टूटा हुआ फर्नीचर व कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर सिस्टम तथा मेजों पर धूल जमी देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और वहां उपस्थित प्रधानाचार्य, संबंधित अधिकारियों व प्रवक्ताओं को व्यवस्थाओं एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कक्षाओं में उपस्थिति पंजिकाओं का भी गहनता के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान प्रकाश में आया कि दो कक्षाओं में अनुपस्थित बच्चों की अनुपस्थिति नहीं लगाई गई थी और कॉलम कई माह से खाली छोड़े गए थे। इस पर मंत्री ने जांच करने के निर्देश दिए।

शहर के मल्टीप्लेक्सों में नहीं हैं चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट

गाजियाबाद : शहर के मल्टीप्लेक्सों में चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट नहीं हैं। दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालयों का इंतजाम भी नहीं हैं। आरओ के पानी की जांच भी नहीं कराई जा रही है। दीवारों की साफ सफाई भी नहीं की जा रही है। ज्यादातर में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालने का भी ठोस इंतजाम नहीं है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश एवं उनकी टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में शहर के 23 मल्टीप्लेक्सों में हेल्थ सेफ्टी से जुड़े इंतजाम बेहद खराब पाए गए हैं। निरीक्षण के साथ ही इन मल्टीप्लेक्सों की हेल्थ सेफ्टी एनओसी रोक दी गई है।

एंजल मॉल से वसूला कर, जारी रहेगी कार्रवाई : नगरायुक्त

साहिबाबाद : संपत्ति कर जमा न कराने वालों के खिलाफ नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम वसुंधरा और मोहन नगर जोन की टीम ने बुधवार को अभियान चलाया। वसूली अभियान के दौरान नगर निगम वसुंधरा जोन की टीम ने 1.36 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर वसूला जबकि मोहन नगर जोन की टीम ने राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई कर दो लाख से अधिक का संपत्ति कर वसूला है। कौशांबी में ग्रीन बेल्ट पर कराए गए अवैध निर्माण को भी जेसीबी से ध्वस्त कराया गया। सुबह अतिक्रमण हटवाने के लिए खुद नगरायुक्त ही कौशांबी पहुंचे थे। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बताया कि संपत्ति कर की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को नगर अपर नगरायुक्त प्रमोद कुमार, निगम वसुंधरा जोन के प्रभारी सुनील राय ने टीम के साथ कौशांबी स्थित एंजल मॉल पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की। वसुंधरा जोनल प्रभारी सुनील राय ने बताया कि कौशांबी स्थित एंजल मॉल में स्थित अलग–अलग प्रतिष्ठानों पर पिछले चार सालों से 1.36 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया था। इस वजह से छह प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

एनजीटी के आदेश के बाद भी नालों का गंदा पानी पहुंच रहा हैं यमुना नदी में

गाजियाबाद : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के बाद भी नालों के जरिए गंदा पानी यमुना नदी में बहाया जा रहा है। यह पानी भू–गर्भ जल को भी खराब कर रहा है। नगर निगम, खोड़ा नगर पालिका के अलावा लोनी नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाले कई बड़े नाले शाहदरा ड्रेन के जरिए यमुना नदी में मिलते है। इसके अलावा एक नाला नगर निगम क्षेत्र से गुजरता हुआ तिलपता ग्रेटर नोएडा के निकट यमुना नदी में जाकर गिरता है। इन नालों के पानी को ट्रीट करने का इंतजाम नाकाफी है। नगर निगम के दो एसटीपी है लेकिन इनके संचालन में लापरवाही पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना तक लगाया जा चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनजीटी में नालों की गंदगी को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। वर्ष 2018 में अभिष्ट कुसुम गुप्ता ने एनजीटी में नोएडा अथॉरिटी, नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। नोएडा के सेक्टर–137 से सटे गांव कौंडली के पास सिंचाई विभाग की एक नहर का जिक्र किया गया । यह नहर यमुना नदी से मिलती है। इस नहर में गाजियाबाद के कुछ नालों का गंदा पानी बहाया जा रहा है।

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative Society Vasundhra,
Ghaziabad (UP)
Mobile +91 8130640011
Email : prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

जिले की सुरक्षा को लेकर पुलिस रही अलर्ट

गाजियाबाद : शहर में बुधवार को पुलिस हाई अलर्ट रही। खात तौर पर कैला भट्टा और मसूरी में पुलिस का पहरा रहा। आइजी रेंज प्रवीण कुमार ने मसूरी थाने पहुंचकर पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस की पीठ भी थपथपाई। दिल्ली में चल रहे उपद्रव को देखते हुए जनपद की पुलिस सतर्क है। बुधवार को आईजी रेंज लोनी से वापस मेरठ लौट रहे थे। मसूरी में पूर्व में कई बार महिलाओं ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया था। मसूरी क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है।

अचानक मसूरी पहुंचे आइजी को देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आइजी ने थाने का निरीक्षण किया और दफ्तर में रखे कुछ रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान सीओ सदर प्रभात कुमार भी थाने पहुंच गए। आइजी ने एसएचओ नरेश कुमार ड्क्षसह और सीओ से क्षेत्र में शांति व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कैला भट्टा में एसपी सिटी ने लोगों के साथ संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील की है।

संयुक्त अस्पताल में हंगामा, बाधित रही ओपीडी

गाजियाबाद : संयुक्त अस्पताल में बुधवार को एक महिला ने हंगामा कर दिया। जिसके चलते लगभग एक घंटे तक ओपीडी बाधित रही और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस के पहुंचने के बाद हंगामा शांत हो सका और ओपीडी फिर से शुरु हो सकी। संयुक्त अस्पताल में दोपहर लगभग 12 बजे एक महिला डॉ. आरसी गुप्ता के केबिन में बिना नंबर के जबरन घुसने लगी। कमरे के बाहर लाइन में लगे अन्य मरीजों ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वह सबको धक्का देते हुए जबरन कमरे में घुस गई, जिस पर हंगामा हो गया।

स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं अधिकारी : सीडीओ

गाजियाबाद : स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और उनके लाभ से लोगों को लाभांवित करने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाने के लिए कहा। इस मौके पर सीडीओ ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी संबंधित अधिकारी इन योजनाओं में गंभीरता दिखाते हुए पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की और कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के संबंध में क्षेत्र में प्रचार–प्रसार भी किया जाए जिससे लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले को कामयाब बनाने व लोगों के उपचार के लिए पूरा प्रयास करें।

एमवाईएस को 40 व केंद्र की पीएमईजीपी को सिर्फ 10 फीसदी ऋण

गाजियाबाद : केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगारी समाप्त करने को विभिन्न योजनाएं पटल पर हैं। वित्तीय वर्ष अगले माह समाप्त हो रहा है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाईएस) के तहत बैंक शाखाओं ने आवेदकों को जहां 40 फीसदी ऋण वितरित किए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) के तहत अभी तक बैंकों ने 10 प्रतिशत लोन पास किए हैं। बैंकों की उदासीनता के चलते केंद्र व प्रदेश सरकार की स्वरोजगार मुहैया कराने वाली योजनाओं को पलीता लगा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, बाबा साहब आंबेड़कर रोजगार प्रोत्साहन योजना व एनआरएलएम योजना शामिल हैं। केंद्र सरकार की पीएमईजीपी व प्रदेश सरकार की एमवाईएस प्राथमिकता वाली योजनाओं में बैंकों की उदासीनता के चलते आवेदकों को ऋण वितरित नहीं किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक स्थिति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की है, जिसमें सिर्फ 10 फीसदी ही ऋण वितरित किए गए हैं।

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.I. Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.